

कानून और न्याय: आवारा कुतों की नसबंदी, टीकाकरण को लेकर याचिका

विनय शैलावत

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीओ कॉन्फ्रेस फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में नोटिस दिया। इस याचिका का उद्देश्य वह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में आवारा कुतों की टीक से नसबंदी और टीकाकरण बिया जाए। न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पुनरावृत्त कर नोटिस जारी करने का यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि अधिकारी आवारा कुतों के लिए कोई प्रभावी नसबंदी या टीकाकरण कार्यक्रम चलाने में विफल रहे हैं (कामबाज इन्ड्रेव व अन्य स्थानों पर भी यही स्पष्ट है)। इससे पहले भी एनजीओ और त्रिवेणी अग्रदमेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने जनहान याचिकाओं के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने याचिका में याचिका नियत्रण (कुतों) नियम, 2001 को लागू रखने की मांग की, जो पशु कूलता नियाशन अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित किए गए थे।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफलता के कारण दिल्ली में आवारा कुतों की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। साथ ही कुतों के कानून के मामले में भी वृद्धि हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिल्ली सरकार की पशुपालन इकाई और दीर्घिण दिल्ली नार नियम के हलनामों से संतुष्ट होकर इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन हलनामों में कहा गया है कि अधिकारी नियमित रूप से आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण कर रहे थे और अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने इस सार्वजनिक समाज के महल पर जारे रखे हुए दिल्ली सरकार और नारायणी अधिकारियों को आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण में प्रयासों को जारी रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ता एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता की ओर से कुतों के कानून के पूर्व प्रकाश डाला गया और दावा किया कि सूचना के अधिकार को प्रतीक्रिया और नसबंदी के प्रयासों की कमी का पता चलाता है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जन जागरूकता के लिए अपनी नसबंदी डेटा को अपने वेबसाइट पर उपलोड करें। प्रदर्शित करें। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि व्यापक नियमित कार्यक्रम ने रुप में आवारा कुतों को पिंजरे में बंद करने की मांग की थी। हालांकि, याचिकाकर्ता संगठनों की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि उनका प्रार्थनिक अनुरोध नसबंदी और प्रासादिक डेटा के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए था।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका में यह माना था कि आवारा कुतों की नियंत्रण के लिए आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है। कॉन्फ्रेस फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा दायर याचिका में पशु कूलता नियाशन अधिनियम, 1960 की धारा 9, 11 और पशु नियंत्रण (कुतों) नियम, 2001 के नियम 3, 5, 6 और 7 के तहत परिकल्पित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए, मध्यवर्ष न्यायालय चांद शर्म और न्यायमूर्ति जनरित सिंह को खड़ा किया जाना था। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने नियंत्रण के लिए आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए सार्वजनिक व्यापार बोर्ड द्वारा आवारा पशु की समस्याओं के उम्मलन के लिए बायोटा है। इससे पूरी गंभीरता से करने की आवश्यकता है। याचिका में आवारा कुतों के लिए नियम 3 (3) नियम 5 (ए) और नियम 6 (2) पशु जन्म नियंत्रण (कुतों) नियम, 2001 के संदर्भ में नियमित "नसबंदी और टीकाकरण" /टीकाकरण कार्यक्रमों को नियमित अंतराल पर करने के लिए नियंत्रण के लिए आवारा कुतों की मांग की गई थी।

नियम 7 के खंड 4 में नियंत्रण देने के लिए याचिका को नियंत्रित करने का प्रावधान है, ताकि उनकी आबादी को नियंत्रित करने का उपयोग करने का आवारा कुतों के लिए आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है। कॉन्फ्रेस फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा दायर याचिका में पशु कूलता नियाशन अधिनियम, 1960 की धारा 9, 11 और पशु नियंत्रण (कुतों) नियम, 2001 के नियम 3, 5, 6 और 7 के तहत परिकल्पित कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए, मध्यवर्ष न्यायालय चांद शर्म और न्यायमूर्ति जनरित सिंह को खड़ा किया जाना था। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने नियंत्रण के लिए आवारा कुतों की नसबंदी और वैधानिक व्यापार बोर्ड को खड़ा किया जाना था। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने नियंत्रण के लिए आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है। इससे भारतीय पशु कूलता बोर्ड द्वारा आवारा पशु की समस्याओं के उम्मलन के लिए बायोटा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कुतों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय संबंधित न्यायीक कार्यक्रमों का आवारा कुतों की नसबंदी और वैधानिक व्यापार बोर्ड को खड़ा किया जाना है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने नियंत्रण के लिए आवारा कुतों के संबंधित करने की आवश्यकता है। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय नियाशन के लिए आवारा कुतों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए सार्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को संबंधित किया जाता है। इससे भारतीय पशु कूलता बोर्ड द्वारा आवारा पशु की समस्याओं के उम्मलन के लिए बायोटा है।

याचिकाकर्ता के लिए नियमित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम सुरक्षा नात्रा उत्तरदाताओं का कर्तव्य है। वैधानिक कर्तव्यों का पालन न करने के कारण, दिल्ली शहर में आवारा कुतों की आबादी में वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप 'कुतों' के कानून के मामलों में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के बकीतों ने दिल्ली के लिए नियंत्रित नगर नियम तथा जावाबदार संस्थाएं अपने कर्तव्यों और कायाक्रमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर में कुतों की आबादी को रोकने के लिए कोई प्रभावी नसबंदी की नहीं किया जा रहा है।

इन नियमों के अनुसार, आवारा कुतों की बड़ी आबादी को कम करने के लिए आवारा कुतों के लिए नियमित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम सुरक्षा नात्रा उत्तरदाताओं का कर्तव्य है। वैधानिक कर्तव्यों का पालन न करने के कारण, दिल्ली शहर में आवारा कुतों की आबादी को मात्रा के साथ वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप 'कुतों' के कानून के मामलों में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के बकीतों ने दिल्ली के लिए नियंत्रित नगर नियम तथा जावाबदार संस्थाएं अपने कर्तव्यों और कायाक्रमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर में कुतों की आबादी को रोकने के लिए कोई प्रभावी नसबंदी की नहीं किया जा रहा है।

यह आबादी एक भयावह रूप से बढ़ रही है, भले ही केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए उठे कोरोडों रुपये आवारा की जारी रहे हैं। उच्च न्यायालय के लिए कोरोडों ने आवारा कुतों की आबादी में वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप 'कुतों' के कानून के मामलों में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के बकीतों ने दिल्ली के लिए नियंत्रित नगर नियम तथा जावाबदार संस्थाएं अपने कर्तव्यों और कायाक्रमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर में कुतों की आबादी को रोकने के लिए कोई प्रभावी नसबंदी की नहीं किया जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडियेंड प्रेस 11, प्रेस काम्पनी, एपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एम्पी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रांथं लालकारा — भरतीय कार्यक्रम समाचार चयन के लिए एपी योगी एकट के लिए नियंत्रित। समस्त न्यायिक कार्यवाहीयों के लिए क्षेत्रान्वित भरतीय योगी एकट के लिए नियंत्रित।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडियेंड प्रेस 11, प्रेस काम्पनी, एपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एम्पी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रांथं लालकारा — भरतीय कार्यक्रम समाचार चयन के लिए एपी योगी एकट के लिए नियंत्रित। समस्त न्यायिक कार्यवाहीयों के लिए क्षेत्रान्वित भरतीय योगी एकट के लिए नियंत्रित।

पाखण्डीबाबाओं से मुक्ति की सार्थक पहल

ललित गर्ग



भारतीय हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एजीपी) की ओर से चौदह महामण्डलेश्वरों और संतों के समाज को मुक्त करने का साराहनीय कदम है। अखाड़ा परिषद की गोपनीय जाच में अखाड़ा से जुड़े ये संत धार्मिक कार्यों पर व्यधिक, दुर्ग, जादू-टोटके व दूसरे अनैतिक कार्यों के भी अपेक्षा लगते हैं। इनके अलावा उत्तावा सौंदर्य और धूमधारा के लिए भी अपेक्षा लगते हैं। अखाड़ा परिषद के लिए गुलाब और गुलाबी रंग की छोटी छोटी संतानों की ओर व्यधिक, दुर्ग, जादू-टोटके व दूसरे संतों के लिए विवाहालाला वाली बाबा जी की ओर व्यधिक, दुर्ग, जादू-टोटके व दूसरे संतों के लिए विवाहालाला वाली बाबा जी की ओर व्यधिक, दुर्ग, जादू-टोटके व दूसरे संतों के लिए विवाहालाला वाली बाबा जी की ओर व्यधिक, दुर्ग, जादू-टोटके व दूसरे संतों के लिए विवाहालाला वाली बाबा ज

